भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 433

दिनांक 22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

भू-खंडों का भू-स्थानिक मानचित्रण

433. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भू-स्थानिक मानचित्रण और अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके भूमि भूखंडों की पहचान को सरल बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसका उपयोग दिल्ली के गांवों में भी किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग): भूमि संसाधन विभाग, दिनांक 01.04.2016 से डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) को कार्यान्वित कर रहा है, जो भारत सरकार से शत-प्रतिशत वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। डीआईएलआरएमपी कार्यक्रम के कार्यकलापों में से एक, भू-कर मानचित्रों का डिजिटलीकरण है जिसमें मौजूदा भू-कर मानचित्रों को जीआईएस-एनकोडेड डिजिटल मोड में परिवर्तित किया जाता है, ताकि अधिकारों के अभिलेखों (आरओआर) में किए गए परिवर्तनों के अनुरूप भू-कर मानचित्रों को अद्यतन करने में सुविधा हो। इसके अलावा, विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भू-खंडों को विशिष्ट आईडी प्रदान करने के लिए विशिष्ट भू-खंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) या भू-आधार नामक एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित किया है। यूएलपीआईएन या भू-आधार, प्रत्येक भू- खंड के शीर्षों के भू-निर्देशांकों पर आधारित 14 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है। अब तक, डीआईएलआरएमपी एमआईस के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने कोई यूएलपीआईएन या भू-आधार सृजित नहीं किया है।

*****